

संक्षिप्त

समाचार



पटना में 140 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार, छिपाकर धूपी से ला रहे थे खेप

पेट्रोल पंप मालिक के घर से 56 लाख रुपये की चोरी

छोड़ती, पटना

पटना। पटना में पुलिस ने 1294.56 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। वहाँ दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। घटना राती तालाब थाना क्षेत्र की है, जहाँ पुलिस ने मद्दा निधि विवाह का सूचना पर बड़ी कारबाही करते हुए कनपा पुल के पास एक ट्रक से 140 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई। एक तस्कर घृणा के दौरान कर्मचारी का दिनकर रखिदास है। दूसरा सीतामढ़ी निवासी सुलील कुमार सहनी है। तस्कर चोरों के बोरों में छिपाकर उत्तर प्रदेश से शराब ला रहे थे। सिटी एस्पी विश्वमी भानू प्रताप सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी है। SDPO पालींगंज और रानींगंज थानाओं के नेतृत्व में वाहन चोरिका अभियान चलाया गया। जांच के दौरान ट्रक से शराब बरामद हुई। राती तालाब थाने में कांड संख्या 267/25 दर्ज की गई है। एक तस्कर घृणा में जाकर पानी भी पिया। वाहन तके दीराम चोरों से घर के बिजली को बोरों को सलाई करना था दोनों गिरफ्तार तस्करों को नायिक विहासत में भेज दिया गया है।

पटना में बाबा साहेब की मूर्ति चोरी, 2007 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने की थी स्थापना

पटना। पटना में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति चोरी हो गई है। पूरा मामला गौरीचक थाना क्षेत्र के जैवर गांव का है। सोमवार सुबह ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिली। मूर्ति की स्थापना 2007 में तत्कालीन



विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई अधिकार थाना क्षेत्र के नायिक विहासत में थी। जैवर गांव के लोकों के गुरुआया लोहा सिंह ने बताया कि यह फाइबर की बनी लगभग 2 फीट ऊंची मूर्ति थी। हर साल बाबा साहेब की

जयंती पर वहाँ माल्याली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था।

जैवर गांव के लोकों के गुरुआया लोहा सिंह ने बताया कि यह प्रारंभिक थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खाली जा रही है। जैवर गांव के रिवाइस टोलों के निवासियों ने बताया कि रिवाइर गत को कुछ असामाजिक तत्वों ने मर्ति चोरी कर फेंक दी। इस घटना से क्षेत्र के महादलित समाज में आकोश है।

मोकामा में नाले में गिरफ्तार मासूम की मौत, घर के पास खेलने के दौरान हादसा

पटना। पटना में खुले नाले में गिरने से डेढ़ साल के मासूम दिलखुरा कुमार की मौत हो गई। घटना मोकाम के इंदिरा नगर क्षेत्र है, जहाँ मिथुन माझी की बेटा रिवाइर के नाम की रात की दिलखुरा घर के पास खेल रहा था।

वह अचानक खुले नाले में गिर गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत नगर निवारक को नाले की सफाई की गई



थी, लेकिन नगर परिषद के कर्मचारी नाले का ढक्कन खुला छोड़कर चले गए। यह नाला काफी गहरा है और पूरे वार्ड का पानी इसी से होकर निकलता है। घटना के बाद चालक के अनुमंडल के चंपापुर के पास की है।

घटना की विवाही रिवाइर की रात लोग खाली आजल कुमार की रहने वाली आजल कुमारी के रूप में हुई है। आजल अपनी मां के साथ बैकट्रॉप जा रही थी। इसी दौरान रॉना साइड से आ रहे एक सड़क बस ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शीयों के उचित रिवाइर के बाद उत्तरक, टक्कर के बाद चालक ने बस को पीछे कर दिया। बस पर कोई नंबर लगता नहीं है।

चालक बस छोड़कर फरार:

दूसरे के बाद चालक बस को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले ने जाम हटा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

डीजे ट्राली के चपेट में आया मजदूर, मौत, ताजिया जल्लु में बेटे को खोजने निकला था 3 बच्चों का पिता



हाजीपुर। हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र में मुहर्म के अवसर पर सोमवार अहले सुबह निकले ताजिया जल्लु के दौरान एक घटना समाप्त हो गई।

दिनी काला पर्वी ओवर ब्रिज पर DJ ट्राली के चबैंके की चोपत में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के दीलतुरु निवासी मालमद जवाहा (35) के रूप में हुई। वह अपना 10 साल का बेटा को खोजने निकला था। मृतक के बेटा जल्लु देवेन आया था। घटना के बाद उसे तुरंत निवासी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह एक लोग था।

मृतक की परिवारी ने बताया कि यह एक लोग था जो अपराधी के बाद उसे निवासी ने बताया कि यह

**भावपूर्ण स्त्री के तौर पर ममता
को कड़े कदम उठाने चाहिए**

कोलकाता के विधि महाविद्यालय प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ कथित रूप से वरिष्ठ छात्रों द्वारा दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दक्षिण कोलकाता के इस परिसर में वह परीक्षा संबंधी प्रवेशप्रभ भरने गई थी। मैटिकल जांच में सामूहिक रैप की पुष्टि होने के साथ ही एक सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार किया गया। पीड़िता की शिकायत के अनुसार उसे जबरन यूनियन रूम में रोका गया और पूर्व छात्र व आपराधिक मामलों के वकील ने रेप किया। दो अन्य छात्रों ने घटना का वीडियो भी बनाया। शिकायतकर्ता ने बताया, दोषी के विवाह प्रस्ताव को वह पूर्व में दुकरा चुकी थी। अभियुक्तों का संबंध तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से बताया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि शैक्षणिक संस्थाओं में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है। मुख्य आरोपी मनोजित के खिलाफ पहले भी कई विवाद सामने आने के बावजूद उसे कॉलेज में अस्थाई नौकरी मिलने के पीछे राजनीतिक संरक्षण बताया जा रहा है। भाजपा घटना पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर रही है जबकि उसे बीएचयू की वह घटना याद रखनी चाहिए जिसमें तमाम दबाव के बाद आरोपियों को पकड़ा गया था। तब सत्ताधारी दल ने किस राजनेता पर कार्रवाई की थी। यह स्वैफनाक है। विभिन्न घटनाओं के आधार पर कहना अतिश्योक्त नहीं है कि देश के शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय छात्राओं के लिए अति असुरक्षित हैं। तमाम नियमों व कानूनी पावंदियों के बावजूद सामने आने वाली ये घटनाएं चुनिदा हैं ज्योकि छात्राएं घबरा जाती हैं ज्योकि उनके शिक्षा ग्रहण करने में अड़ंगे लगने लगते हैं। सवाल छात्राओं का ही नहीं है, महिलाओं/बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सरकारी व प्रशासनिक दुलमुल रवैया बदल वर्त्यों नहीं रहा। महिलाओं के प्रति अपराध थामने के लिए किए जाने वाले प्रचार, आयोग व दीवारों पर लिखे स्लोगन काफी नहीं कहे जा सकते। राजनीति को शिक्षा से दूर रखने की बात दशकों से होती रही है। उस पर राजनेताओं के अनर्गल बयानों से पीड़िता व उसके परिवार-परिवर्तियों को होने वाले मानसिक कष्ट की भरपाई कैसे हो सकती है। कोलकाता के मेडीकल कॉलेज में यूनियर डॉक्टर के जघन्य रैप/हत्या के जख्म अभी ज्यों-के-त्यों हैं। ममता बनर्जी को राजनीति को हाशिए में ढकेलते हुए भावपूर्ण लड़ी के तौर पर कड़े कदम उठाने से चूकना नहीं चाहिए।



पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

वामपंथी उग्रवाद का हिस्सा शहरी नक्सली, एक ऐसा मुहावरा जिसने हाल के वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है, शहरी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को संदर्भित करता है जो माओवादी उग्रवाद के साथ सहानुभूति रखते हैं, उसका समर्थन करते हैं। शहरी नक्सली भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है और शत्रुतापूर्ण देशों में उनके कई समर्थक हैं, जिनके साथ कई वर्षों से छद्य युद्ध लड़ रहे हैं। ये शहरी नक्सली स्थानीय विरोध को खरीदने की चाहत रखने वाले वैश्विक व्यापारिक दिग्गजों की तरह भारत के खिलाफ अपने हमले के आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख माध्यम हैं। ये शहरी समर्थक छद्य बुद्धिमान, अच्छे वक्ता होते हैं और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद या मानवाधिकार अधिवक्ता बताते हैं, लेकिन उनका असली लक्ष्य युद्ध, भले-भाले दिग्गजों को भर्ती करके और माओवादी प्रचार करके देश को अस्थिर करना है एनआईए के अध्ययन के अनुसार, कई फ्रंटल संगठन और छात्र विंग इस भौतिक प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं। ये संगठन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की आदर्शविदिता और कमज़ोरी का फायदा उठाते हैं। वे सामाजिक न्याय के पैरोकार बनकर छात्रों को कट्टरपंथी मान्यताओं से भर्ती देते हैं, उन्हें सरकार का विरोध करने और हिंसक, विद्रोही जीवनशैली अपनाने के लिए

वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ मोदी सरकार का विकास मॉडल और प्रतिवाद रणनीति

मजबूर करते हैं। इस जहारीली मानसिकता या विचारधारा के परिणामस्वरूप हम एक समाज और राष्ट्र के रूप में बहुत पीड़ित हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में भारत की बहुआयामी वामपंथी उग्रवाद विरोधी नीति, जो सुरक्षा प्रवर्तन, समावेशी विकास और सामुदायिक भागीदारी को जोड़ती है, एक बड़ी सफलता रही है। आंदोलन धीरे-धीरे कम हो गया है, हिंसा में काफी कमी आई है और कई वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में फिर से शामिल किया जा रहा है। भारत सरकार 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वामपंथी उग्रवाद का छत्तीसगढ़, झारखण्ड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे राज्यों के कुछ इलाकों पर प्रभाव पड़ा है। दशकों से उग्रवाद से संबंधित रक्तपात ने पूर्वोत्तर में जीवन को दबा दिया था। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने महत्वपूर्ण उग्रवादी संगठनों के साथ 12 शांति संधियों पर बातचीत की है और 10,000 से अधिक विद्रोहियों ने अपने हथियार डाल दिए। मुख्यधारा के जीवन में प्रवेश किया है। बोडो शांति समझौता और बूरियांग पुनर्वास संधि जैसे ऐतिहासिक समझौतों ने न केवल शांति बहाल की, बल्कि इस क्षेत्र को मुख्यधारा में फिर से शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की। हाल ही में त्रिपुरा में एनएलएफटी और एटीएफ के साथ 2024 के समझौते ने 35 साल की लड़ाई को समाप्त कर दिया। इन ऐतिहासिक पहलों ने न केवल शांति में सुधार किया है, बल्कि स्थानीय समुदायों में विश्वास भी बढ़ाया है। इस शांति-केंद्रित दृष्टिकोण के स्पष्ट परिणाम के रूप में संस्कृत बल विशेषाधिकार अधिनियम को पूरे पूर्वोत्तर में कम कर दिया गया है। 2014 और 2024 के बीच, हिंसक घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई है। नरेन्द्र मोदी की सरकार ने नीतिगत सुधारों को भी लागू किया। 2015 में लुक ईंस्ट से एक्टर ईंस्ट नीति में परिवर्तन ने पूर्वोत्तर को एक सुदूर सीमा से दक्षिण-पूर्व एशिया के एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वारा में बदल दिया। कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और बांग्लादेश के साथ अग्ररतला-अखौरा रेल लिंक जैसी प्रमुख पहलों व्यापार और गतिशीलता बढ़ाने के लिए सीमा पार केनेशन बना रही है। क्षेत्र का सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। पहले नजरअंदाज किए गए पूर्वोत्तर भारत के समझौते सांस्कृतिक अतीत की अब राष्ट्रीय और विश्वव्यापी स्तर पर सराहना हो रही है। नॉर्थ ईंस्ट जोन कल्चरल सेंटर जैसे सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना ने नगालैंड के हॉर्न्सबिल और मणिपुर के संगाई जैसे क्षेत्रीय त्योहारों को बढ़ावा दिया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में चोराइदों के मोइदाम के शिलालेख ने क्षेत्र के सांस्कृतिक गैरव को बढ़ा दिया है। मुगा सिल्क, जोहा चावल, तेजपुर लीची, काजी नेमू और बोका चौल जैसे स्थानीय उत्पादों ने जीआई लेबल प्राप्त किए हैं, जिससे उनकी दृश्यता और आर्थिक मूल्य बढ़ गया है। इस पुनर्जीवित सांस्कृतिक पहचान और उत्तम बुनियादी ढांचे के परिणामस्वरूप पर्यटन फल-फूल रहा है। अकेले 2023 में इस क्षेत्र में लगभग 1.20 करोड़ घरेलू पर्यटक और 2.21 लाख विदेशी आगंतुक थे। पूर्वोत्तर भारत में कृषि, जो पहले अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद कम प्रदर्शन से सीमित थी, एक शानदार बदलाव के दौर से गुजर रही है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट जैसे विशिष्ट प्रयासों से 1.89 लाख से अधिक किसानों को सीधे लाभ हुआ है, जिसने 1.73 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को जैविक खेती में बदल दिया है। इन किसानों को और सशक्त बनाने के लिए '10,000 एफपीओ' के गठन और संवर्धन' पहल के हिस्से के रूप में 205 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित किए गए हैं, जो क्षेत्र के 15,500 किसानों को कवर करते हैं। ये एफपीओ सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करते हैं, प्रसंस्करण कौशल में सुधार करते हैं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच को व्यापक बनाते हैं। भारत सरकार सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की खामियों को दूर करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) नामक एक विशेष योजना के अंतर्गत क्रमशः सबसे अधिक प्रभावित जिलों और चिंता के जिलों को 30 करोड़ और 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, विभिन्न जिलों के लिए उनकी जरूरतों के आधार पर अनूठी पहल प्रदान की जाती है। वामपंथी उग्रवाद की हिस्क घटनाएं, जो 2010 में 1936 के शिखर पर थीं, 2024 में 374 तक पिछे गई हैं, जो 81 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। इसी तरह कुल मौतों की संख्या भी इस दौरान 85 प्रतिशत कम हुई है, जो 2010 में 1005 से 2024 में 150 हो गई है। भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पहला, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में कानून का शासन स्थापित करना और सभी अवैध हिंसक कृत्यों को समाप्त करना। दूसरा, लंबे समय तक नक्सली आंदोलन के परिणामस्वरूप विकास से विचित क्षेत्रों में तुकसान की शीघ्र भरपाई करना। वामपंथी उग्रवाद के खतरे से समग्र रूप से निपटने के लिए, वामपंथी उग्रवाद के लिए एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को 2015 में मंजूरी दी गई थी। इसमें एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है जिसमें सुरक्षा उपाय, विकास पहल, स्थानीय लोगों के अधिकारों और पात्रता की रक्षा आदि शामिल हैं। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 61 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 178 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चालू किए गए हैं। कौशल विकास योजना का विस्तार सभी 48 जिलों में किया गया। सुरक्षा बलों के लिए 1,143 आदिवासी युवाओं की भर्ती की गई। 2019 से अब तक सुरक्षा की कमी को पूरा करने के लिए 280 नए कैप स्थापित किए गए हैं, 15 नए संयुक्त कार्य बल बनाए गए हैं और विभिन्न राज्यों में राज्य पुलिस की मदद के लिए 6 सीआरपीएफ बटालियन भेजी गई हैं। इसके साथ ही नक्सलियों के वित्त को काटने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सक्रिय करके एक आक्रामक योजना लागू की गई है, जिसके परिणामस्वरूप उनके लिए वित्तीय संसाधनों की कमी हो गई है। नक्सलियों को घेने और उन्हें भागने से रोकने के लिए कई लंबी अवधि के ऑपरेशन किए गए। दो अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने ज्ञारखंड से 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' की शुरुआत की। यह पहल 15,000 से अधिक गांवों में पूर्ण ग्रामीण संरचित के लिए व्यक्तिगत सुविधाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, जिससे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की मदद होगी। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित समुदायों में, सरकार 3-सी कनेक्शन बढ़ा रही है, जिसमें सड़क, मोबाइल और वित्तीय संपर्क समिल हैं। 2014 में 330 पुलिस स्टेशन ऐसे थे, जहां नक्सली घटनाएं हुईं, लेकिन अब यह संख्या घटकर 104 रह गई है। पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र 18,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक था, लेकिन अब यह केवल 4,200 वर्ग किलोमीटर रह गया है। 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा के 16,463 मामले सामने आए। हालांकि, 2014 से 2024 के बीच हिंसक घटनाओं की संख्या में 53 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 7,744 पर हुंच गई है। इसी तरह, सुरक्षा बलों के हताहतों की संख्या में 73 प्रतिशत की कमी आई है, जो 1,851 से घटकर 509 हो गई है। 2014 तक 66 किलोबंद पुलिस स्टेशन थे, लेकिन पिछले दस सालों में यह संख्या बढ़कर 612 हो गई है। पिछले पांच सालों में 302 नए सुरक्षा कैप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत के बहुआयामी अभियान ने उग्रवाद को क्षेत्रीय और परिचालन दोनों ही दृष्टि से बुरी तरह से कमज़ोर कर दिया है।

हैं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच को व्यापक बनाते हैं। भारत सरकार सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की खामियों को दूर करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) नामक एक विशेष योजना के अंतर्गत क्रमशः सबसे अधिक प्रभावित जिलों और चिंता के जिलों को 30 करोड़ और 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, विभिन्न जिलों के लिए उनकी जरूरतों के आधार पर अनूठी पहल प्रदान की जाती है। वामपंथी उग्रवाद की हिंसक घटनाएं, जो 2010 में 1936 के शिखर पर थीं, 2024 में 374 तक पिर गई हैं, जो 81 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। इसी तरह कुल मौतों की संख्या भी इस दौरान 85 प्रतिशत कम हुई है, जो 2010 में 1005 से 2024 में 150 हो गई है। भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पहला, नवसल्लावाद प्रभावित क्षेत्रों में कानून का शासन स्थापित करना और सभी अवैध हिंसक कृत्यों को समाप्त करना। दूसरा, लंबे समय तक नवसल्ली आंदोलन के परिणामस्वरूप विकास से वंचित क्षेत्रों में नुकसान की शीघ्र भराई करना। वामपंथी उग्रवाद के खतरे से समग्र रूप से निपटने के लिए, वामपंथी उग्रवाद के लिए एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को 2015 में मजूरी दी गई थी। इसमें एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है जिसमें सुरक्षा उपाय, विकास पहल, स्थानीय लोगों के अधिकारों और पात्रता की रक्षा आदि शामिल हैं। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 61 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 178 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चालू किए गए हैं। कौशल विकास योजना का विस्तार सभी 48 जिलों में किया गया। सुरक्षा बलों के लिए 1,143 आदिवासी युवाओं की भर्ती की गई। 2019 से अब तक सुरक्षा की कमी को पूरा करने के लिए 280 नए कैप स्थापित किए गए हैं, 15 नए संयुक्त कार्य बल बनाए गए हैं और विभिन्न राज्यों में राज्य पुलिस की मदद के लिए 6 सीआरपीएफ बटालियन भेजी गई हैं। इसके साथ ही नवसल्लियों के वित्त को काटने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सक्रिय करके एक आक्रामक योजना लागू की गई है, जिसके परिणामस्वरूप उनके लिए वित्तीय संसाधनों की कमी हो गई है। नवसल्लियों को घेरने और उन्हें भागने से रोकने के लिए कई लंबी अवधि के ऑपरेशन किए गए। दो अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड से 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' की शुरुआत की। यह पहल 15,000 से अधिक गांवों में पूर्ण ग्रामीण संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत सुविधाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, जिससे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की मदद होगी। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित समुदायों में, सरकार 3-सी कनेक्शन बढ़ा रही है, जिसमें सड़क, मोबाइल और वित्तीय संपर्क शामिल हैं। 2014 में 330 पुलिस स्टेशन ऐसे थे, जहां नवसल्ली घटनाएं हुईं, लेकिन अब यह संख्या घटकर 104 रह गई है। पहले नवसल्ल प्रभावित क्षेत्र 18,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक था, लेकिन अब यह केवल 4,200 वर्ग किलोमीटर रह गया है। 2004 से 2014 के बीच नवसल्ली हिंसा के 16,463 मामले सामने आए। हालांकि, 2014 से 2024 के बीच हिंसक घटनाओं की संख्या में 53 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 7,744 पर पहुंच गई है। इसी तरह, सुरक्षा बलों के हताहों की संख्या में 73 प्रतिशत की कमी आई है, जो 1,851 से घटकर 509 हो गई है। 2014 तक 66 किलोवाट पुलिस स्टेशन थे, लेकिन पिछले दस सालों में यह संख्या बढ़कर 612 हो गई है। पिछले पांच सालों में 302 नए सुरक्षा कैप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत के बहुआयामी अभियान ने उग्रवाद को क्षेत्रीय और परिचालन दोनों ही दृष्टि से बुरी तरह से कमज़ोर कर दिया है।

पर्यावरण के रचनात्मक प्रशासन के जरिए सतत् हरित बदलाव

भूपेंद्र यादव

पर्यावरण कुजनेट्स वक्र
 (एनवायरनमेंट कुजनेट्स कर्व) से
 हासिल पर्यावरण के प्रशासन से जुड़ा
 पारंपरिक ज्ञान यह मानता है कि देश
 पहले विकास करते हैं और बाद में
 सफाई में जुटते हैं। यह अनुभवजन्य
 अंतर्दीष्ट अब विकसित हो चुके उन
 देशों के अनुभवों से प्रेरित है, जिन्होंने
 विकास की प्रक्रिया में संसाधन
 संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु देश
 और विदेश में प्राकृतिक पर्यावरण का
 दोहन किया। लेकिन ऐसी सुविधा
 भारत जैसे देशों को नसीब नहीं है,
 जिन्हें अपनी विशाल आबादी की
 विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा
 करने के लिए अभी भी तेज गति से
 विकास करने की जरूरत है। जब
 2014 में एनडीए सत्ता में आई,
 तो चुनौती हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री
 नरेन्द्र मोदी के मूल सिद्धांतों - सुधार,
 प्रदर्शन और बदलाव - पर आधारित
 विकास एवं प्रगति को गति देने की थी।
 इन सिद्धांतों में जरूरत के हिसाब से
 पर्यावरण की सुरक्षा के सब्जेक्ट उपर्याप्त
 से समझौता किए बिना 'व्यवसाय
 करने में आसानी की सुविधा प्रदान
 करते हुए तेजी गति से विकास करना
 शामिल था। आज 2025 में, हम न
 सिफेर इस चुनौती से निपट पाने में
 सफल रहे हैं बल्कि हमने शासन का

एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसे सारी दुनिया ने माना है। प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ़ था: इस प्रणाली को एक ऐसी प्रणाली में बदला जाए जो इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद हो। वर्ष 2014 में 'स्वच्छ भारत मिशन' की शुरुआत हमारी पहली बड़ी पहल थी। यह पहल स्वच्छता से आगे बढ़कर कचरे के प्रबंधन व पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करने तक जा पहुंची। इस मिशन ने पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को सामाजिक विकास के साथ जोड़ने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाया। इस मिशन को सभी नागरिकों को शामिल करते हुए एक जन आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था और एक स्वच्छ एवं संसाधन के मामले में अपेक्षाकृत अधिक कुशल भारत की चाहत को आगे बढ़ाया गया था। विभिन्न शहरों में नागरिकों को पारदर्शी तरीके से वास्तविक समय में वायु की गुणवत्ता की निगरानी से जुड़ी सुविधा प्रदान करने के तुंत बाद राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया गया। वर्ष 2014 में शुरू की गई 'मेक इन इंडिया पहल' में भी कड़े पर्यावरण अनुपालन मानकों को शामिल किया गया। इससे यह साबित हआ कि हम इकोलॉजी की स्थिरता को बनाए रखते हुए मैन्यूफॉर्मिंग को अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर और तेज गति से बढ़ावा दे सकते हैं। ऊर्जा संबंधी दक्षता को बढ़ावा देने और ऊर्जा पर आधारित अधिक संख्या में उद्योगों को शामिल करने के उद्देश्य से 2015 में प्रदर्शन, उपलब्ध और व्यापार (पीएटी) योजना का विस्तार किया गया। इससे ऊर्जा संबंधी दक्षता के लिए एक बाजार-आधारित तंत्र का निर्माण हुआ। कचरे के कारबरों प्रबंधन, संसाधन संबंधी दक्षता में बढ़ोत्तरी और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 से कचरे के प्रबंधन के सभी प्रमुख नियमों को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण का बुनियादी सिद्धांत बाजार आधारित तंत्र और प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत पर आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से जुड़े ढांचे पर निर्भरता में निहित है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, ई-कचरा प्रबंधन नियम तथा टायर, बैटरी एवं प्रयुक्ति तेल अपशिष्ट प्रबंधन नियम आदि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर तैयार किए गए थे। इससे एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण हुआ, जिसके तहत विभिन्न सामग्रियों के लागभाग 4,000 पुनर्चक्रणकर्ताओं के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र से हटाकर

औपचारिक क्षेत्र में लाया गया है। इस कदम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1600 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 में शुरू किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तराधित्व (ईपीआर) पोर्टल चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 61,055 उत्पादकों ने प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-कच्चा, बेकार टायर, बैटरी के कचरे और प्रयुक्त तेल के क्षेत्र में काम करने हेतु ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। अपशिष्ट नियम, 2022 के प्रकाशन और ईपीआर पोर्टल की शुरूआत के बाद, शोधित अपशिष्ट की मात्रा वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन नियमों के प्रकाशन से पहले 3.6 एमएमटी प्रति वर्ष की तुलना में बढ़कर 127.48 एमएमटी प्रति वर्ष हो गई है। यह सभी हितधारकों के सहयोग एवं समर्थन से संभव हुआ है। प्रक्रियागत दरी में कमी लाने और एक व्यापक पर्यावरणीय मूल्यांकन करने के उद्देश्य से 2018 में 'परिवेश (प्रो-एक्टिव एंड रिसॉन्सिल फैसिलिटेशन बाई इंटरएक्टिव, वर्चुअल एंड एनवायरनमेंटल सिंगल-विंडो हब) नाम के एक ऑनलाइन आईटी टूल का शुभारंभ किया गया। प्रथानमंत्री मोदी के 'डिजिटल इंडिया' के विजन

साकार करते हुए, इस डिजिटल एफर्म ने व्यवसाय जगत और वरेण नियामकों के बीच के संवाद क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। वरेण ने पर्यावरण संबंधी मंजूरी बोझिल एवं कागज-आधारित नया को एक सुव्यवस्थित एवं बूत डिजिटल अनुभव में बदला है। इस ट्रॉटिकोण ने जहां वरेण से जुड़े सख्त मूल्यांकन बनाए रखा है, वहीं इस प्रक्रिया लगने वाले समय में काफी कमी दी है और पारदर्शिता को बढ़ाया वर्ष 2019 में शहरों पर केन्द्रित योजनाओं से लैस 'राष्ट्रीय छवि वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) आधिकारिक शुभारंभ ने हमें नीति दी एवं नियामक से बदलकर ल करने वाला बना दिया है। सीएपी का लक्ष्य 2025-26 तक 10 सांद्रता में 40 प्रतिशत की लाना या आधार वर्ष 2017- की तुलना में 60 माइक्रोग्राम प्रति मीटर के राष्ट्रीय मानक को हासिल ना है। एनसीएपी के साथ-साथ सीधी लानी ने एनसीएपी के तहत आने वाले 131 शहरों में वायु की गुणवत्ता रुझान की बारीकी से निगरानी की जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे वायु की गुणवत्ता निरंतर बेहतर है। वर्ष 2021 में, गैर-प्राप्ति वाले शहरों में वायु गुणवत्ता के नियमन हेतु

पोर्टेल (पीआरएनए) को कागज रहित परियोजना प्रबंधन के एकल बैंदु वाले वेब-आधारित उपकरण वे रूप में शुरू किया गया। इससे स्वच्छता वायु से जुड़े उपायों के कार्यान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रणालि पर नजर रखना संभव हो सकेगा। जुलाई, 2022 से एकल उपयोगी वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध और 3 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रो रेस्ट्रिक्शन पर अधिक मोटाई वाली प्लास्टिक शीर्षक पर प्रतिबंध ने जहां पर्यावरण के क्षेत्र में साहसिक नेतृत्व का परिचय दिया वही उसी वर्ष शुरू किए गए 'जल जीवन' मिशन ने पानी की सुलभता के पर्यावरणीय स्थिरता के साथ जोड़ा। एक व्यापक 'भारत शीतलन कार्योजना' विकसित करके भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। इस कार्योजना में विभिन्न क्षेत्रों के शीतलन संबंधी जरूरतों को पूरा करने का समावेश है तथा इसमें ऐसे कार्यों का समाप्ति दी गई है, जो शीतलन से जुड़े समागम को कम करने में सहायक हैं। विभिन्न क्षेत्रों में शीतलन की जरूरत होती है तथा यह आर्थिक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों कोल्ड-चेन, प्रशीतन, परिवहन और उद्योग जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी जरूरत पड़ती है।

बदलने लगे पाकिस्तान के सुर, उठने लगी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने की मांग

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

जो प्रतिबंध लगाए गए, वह अब भी निरंतर है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की ओर से विश्वास बहाली के उपाय के रूप में 'जांच के दायरे में आए व्यक्तियों' को भारत को प्रत्यर्पित करने में कोई आपत्ति नहीं होने की बात कही है, वह बहुत ही गौर करने लायक है। पाकिस्तान पोपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल का कहना है कि लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को संभावित समझौते और सद्द्वावनार्पण रुख के तहत भारत को प्रत्यर्पित करने के बारे में विचार किया जा सकता है। पाकिस्तान हाफिज और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन जरूरी यह है कि इसके लिए नई दिल्ली का पूरा सहयोग मिले। यहां बिलावल यह दावा करते हुए भी दिखे कि पाकिस्तान के साथ एक व्यापक वार्ता के हस्से के रूप में, जहां आतंकवाद उन मुद्दों में से एक है जिन पर हम चर्चा करते हैं, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इनमें से किसी भी चीज का विरोध नहीं करेगा। राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण (नैक्टा) के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा



और जैश-ए-मोहम्मद दोनों को पाकिस्तान ने प्रतिबंधित कर रखा है, जबकि 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मुख्य पट्टयंत्रकारी हाफिज सईद वर्तमान में आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए 33 साल की सजा काट रहा है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित अजहर को भी नैकटा ने प्रतिबंधित कर रखा है। पर इन दोनों आतंकियों के बारे में यहां हकीकत क्या है, वह किसी से आज छिपा हुआ नहीं है। कहना होगा कि भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक अजहर का नाम भारत में कई बड़े हमलों से जुड़ा है, जिसमें 2001 का संसद हमला, 26/11 का मुंबई हमला, 2016 का पठानकोट एयरबेस हमला और 2019 का पुलवामा आतंकघाती हमला शामिल है। इसके अलावा भी अन्य कई हमलों में

नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के शुरुआती सालों में पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करते हुए 25 दिसंबर, 2015 को ही अचानक पाकिस्तान पहुंचने में संकोच नहीं किया, उस दिन वे तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पोती की निकाह में भी शामिल हुए थे। उन्होंने नवाज शरीफ को अफगानिस्तानी स्टाइल का गुलाबी साफा भी तोहफे में दिया था, जिसे शरीफ पहने हुए भी नजर आए थे। कूटनीति की मेज पर शांति बहाली के प्रयास किए गए, पर हर बार पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत के विश्वास को तोड़ा। जिसके बाद भारत सरकार का यह स्पष्ट मत बना है कि वह पाकिस्तान के साथ आगे की कोई भी चर्चा केवल आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर ही करेगा। भारत ने आज पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने के साथ ही अटारी-बाघा सीमा क्रॉसिंग बंद करना, आयात-नियंत्रण को पूरी तरह से रोकना, अपना हवाई क्षेत्र बंद करने जैसे कई प्रतिबंध आतंकवाद के विरोध में भारत ने पाकिस्तान पर लागू किए हैं। ऐसे में स्वभाविक है कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान

प्रियुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल ने आज कह रहे हैं, वह बहुत नम हो जाता है, क्योंकि इस बात ने अभी एक माह भी नहीं हुआ, जब उन्होंने भारत के खिलाफ तमकर जहर उगला था। बिलावल भारत को चेतावनी दे रहे थे कि भगर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो देश के लिए उद्ध ही एकमात्र विकल्प रह जाएगा। हाँ तक कि बिलावल के नेतृत्व एक उच्चस्तरीय पाकिस्तानी संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत के साथ संघर्ष करने की बात कहने बाद अपने देश का पक्ष रखने लिए वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और बंद पहुंचा था। यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में भारी बेड्जटी के बाद यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने बरगलाने के लिए ब्रसेल्स भी हुंचा। जहां अमेरिका की तरह ही राप में कई सांसदों और जिममेदार दाधिकारियों ने पाकिस्तान से नापाए इस प्रतिनिधिमंडल के समक्ष भातकवाद का साथ छोड़ने और भातकवादियों को भारत प्रत्यापित नरने को कहा था। भारत ने भी निया को यह सुपष्ट संदेश दे दिया कि पाकिस्तान के साथ पानी पैर खून एक साथ नहीं बहाए जा सकते।

रातोरा कर रहे व्यापकों का लिए आज नई मान प्रसारण होगा , जिससे उनकी अर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। कर्ज में दूबे हुए व्यक्तियों को आज कर्ज से राहत मिलने वाली है। आज आप किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन कर सकते हैं।

तुला राशि: आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज आपको व्यापार में बड़ा धन लाभ होगा, जिससे आपको भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। अविवाहित व्यक्तियों को आज, विवाह के लिए अच्छा रिश्ता आएगा, जिन लोगों को अच्छे घर फैलैट की तलाश थी, आज उनको बढ़िया डील मिलेगी।

वृश्चिक राशि: आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज आप टीवी डिबेट में बहुत अच्छे से परकर्फेम करेंगे, विरोधियों को अपने सामने टिकने नहीं देंगे। नौकरी का इंतजार कर रहे व्यक्तियों को, आज अच्छा ऑफर मिलेगा। आज आप ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने-लिखने में बिताएंगे। छात्र जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा।

धनु राशि: आज का दिन आपके अनुरूप रहेगा। आज आपको बिजनेस में बड़ा आर्डर मिलने की संभावना है। किसी शरीरिक समस्या से आपको निजात मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, बच्चों के साथ आज आप डिनर पर जायेंगे। साइबर सुरक्षा से जुड़े व्यक्तियों को आज एक अहम जानकारी मिलेगी।

मकर राशि: आज का दिन मिला-जुला रहेगा। व्यापारिक दृष्टि से आज आपको धन लाभ होगा, परिवारिक माहील खुशनुमा बना रहेगा। आज आपके बच्चे आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, आपको उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए।

कुंभ राशि: आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आपको बिजनेस में बड़ा धन लाभ होगा, अर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज आपमें कमाल का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे। कला जगत से जुड़े हुए व्यक्तियों को आज किसी अनुभवी व्यक्ति से सम्मान प्राप्त होगा।

मीन राशि: आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। आज आप अपने बेटे के साथ मिलकर व्यापार को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। आज आप किसी सामूहिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। आज आपको मानसिक उलझन से राहत मिलेगी, जिससे आपका काम में मन लगेगा।

Supreme Court ready to hear Bihar voter list revision case, hearing on July 10

New Delhi, The Supreme Court has agreed to hear the petitions challenging the Special Intensive Revision (SIR) of the voter list in Bihar. The Supreme Court will hear these petitions on July 10. On Monday, lawyers Kapil Sibal, Abhishek Manu Singhvi, Gopal Shankarnarayanan and Shadan Farasat, on behalf of the petitioners, mentioned before the vacation bench headed by Justice Sudhanshu Dhulia and demanded an early hearing on the petitions. These lawyers said that if a voter in Bihar is unable to provide the documents, then his name can be removed from the voter list. Singhvi said that there are 8 crore voters in Bihar and out of them, 4 crore have to be thoroughly revised, this is an impossible task. When Kapil Sibal said that the timeline is very strict. If you are not able to submit the documents by July 2, then you will be out of the voter list. Then Justice Dhuliya said that the timeline has no validity, because the notification of the election has not been issued



yet. After that the court ordered to hear these petitions on July 10. In this case, apart from Rashtriya Janata Dal (RJD), Trinamool Congress (TMC), Association for Democratic Reforms (ADR) has filed petitions in the Supreme Court. The petition has demanded the cancellation of the Election Commission's order issued for SIR in Bihar. Advocate Prashant Bhushan, on behalf of ADR, has filed a petition saying that this order of the Election Commission is arbitrary. The petition states that this order of the Election Commission is a violation of Articles 14, 19, 21, 32 and 326 of the Constitution as well as the Representation of the People Act. The petition states that this order of the Election Commission also violates Rule 21A of the Voter Registration Rules. The last such revision in Bihar was done in 2003

The petition states that the order of the Election Commission is not only arbitrary, but it has been issued without due process. This may deprive lakhs of voters of their right to vote. This move of the Election Commission will hamper free and fair elections. The time limit for the special intensive revision of the voter list is unreasonably short, as there are lakhs of citizens in the state whose names were not in the 2003 voter list and who do not have the documents sought under the order of the special intensive revision. The petition states that some people may be able to obtain these documents, but the very short time limit for the special intensive revision may prevent them from doing so in time. The petition states that Bihar is a state where poverty and migration are at a high level and a large population here does not have necessary documents like birth certificates or records of their parents. The last such revision in Bihar was done in 2003

Rain becomes a problem in Delhi: Office goers are troubled due to waterlogging and traffic jam

New Delhi, On one hand, the rain in the capital Delhi on Monday morning brought relief from the heat, but on the other hand it also created many problems for the people. Waterlogging and heavy traffic jams were seen in many areas, due to which people had to face difficulties in commuting. As soon as the rain stopped, the crowd gathered on the roads of Delhi. The traffic on the road coming from Gurugram to Delhi has started increasing gradually. At the same time, the speed of vehicles on the route going from Delhi to Gurugram is also slow. Since it is Monday and most of the people leave for office, immediately after the rain stopped, traffic



jams were seen at many places on the roads. There was a traffic jam of several kilometers on the road from Daula Kuan to Gurugram Airport. People coming from Mahipalpur and Delhi Cantt were badly stuck in the jam. There was a long jam on MB Road in Sangam Vihar area due to waterlogging. In the pictures of around

9:30 am on Monday, it can be seen that the road is flooded with a lot of water and the speed of vehicles has completely stopped. Local people say that due to this jam, they are getting late in reaching the office. This problem has become common here after every rain, but no permanent solution has been found.

Some people in Sangam Vihar area told news agency IANS, "There is a lot of trouble due to waterlogging. There are many potholes on the roads, the roads are not built properly." However, at some places in Delhi, workers were seen pumping out water. Talking to IANS, a worker said, "We have been working since 5 am. We have not allowed waterlogging in this area. Earlier, there used to be water everywhere here." According to the Meteorological Department, similar rains will continue in Delhi-NCR for the next few days. In such a situation, citizens have been advised to leave home early and keep an eye on traffic updates.

Enthusiasm among devotees for Amarnath Yatra, number of visitors crosses 70 thousand in 4 days

Srinagar, There is tremendous enthusiasm among the people regarding the Amarnath Yatra. In the last four days, more than 70 thousand devotees performed the Amarnath Yatra, while another batch of 8,605 pilgrims left for the Kashmir Valley on Monday. According to officials, since the Amarnath Yatra started on July 3, about 70 thousand people have visited Baba Barfani so far. Out of these, 21,512 pilgrims had darshan on Sunday. Apart from this, another batch of 8,605 pilgrims left for the Kashmir Valley from Bhagwati Nagar Yatri Niwas in Jammu in two security convoys on Monday. Officials said the first convoy



carrying 3,486 pilgrims is going to Baltal base camp in north Kashmir, while the second convoy carrying 5,119 pilgrims is going to Nunwan (Pahalgam) base camp in south Kashmir. Shri Amarnath Ji Shrine Board (SASB) officials said that apart from the pilgrims arriving at Bhagwati Nagar Yatri Niwas in

Jammu, many devotees are directly reaching Baltal and Nunwan (Pahalgam) for spot registration to join the yatra. 180 additional companies of CAPF have been brought in to augment the existing strength of Army, BSF, CRPF, SSB and local police. The entire route has been secured by security forces.

The local people have extended full support to this year's Amarnath Yatra as they have been doing in the past as well. To send a message that Kashmiris are hurt by the Pahalgam terror attack, the local people were the first to welcome the pilgrims of the first batch. As soon as the pilgrims crossed the Nowgam tunnel and entered the Kashmir

Valley from Qazigund, the local people gave them a warm welcome. On Sunday, locals served cold drinks and pure drinking water to pilgrims returning from Baltal base camp in Ganderbal district of north Kashmir. The pilgrims accepted the hospitality of the locals without hesitation and thanked the Kashmiris for this love. The Amarnath Yatra began on July 3 and will end on August 9 after 38 days. Shri Amarnath Ji Yatra is one of the most sacred religious pilgrimages for the devotees, as the legend goes that Lord Shiva revealed the secrets of eternal life and immortality to Mata Parvati inside this cave.

Former Punjab minister Bikram Singh Majithia sent to 14-day judicial custody, Nabha jail

Mohali, Former Punjab minister Bikram Singh Majithia has been taken to Nabha jail amid tight security. Majithia's remand ended on Sunday, after which he was produced in the court. The Mohali court has sent him to 14 days judicial custody. Shiromani Akali Dal leader and former minister Bikram Singh Majithia was arrested on 25 June in the drug money laundering case. Punjab's Vigilance Bureau arrested Majithia from his house in Amritsar. The next day the court sent him on 7-day remand, which was later extended for 4 days.



Currently, after the remand ended, Majithia appeared in Mohali court on Sunday, a holiday. Government lawyer Ferry Sofat told news agency IANS, the total remand was for 15 days. 12 days have passed, but the vigilance department has kept 3 days in reserve so that if needed, interrogation can be done later. The lawyer said that vigilance teams are conducting raids at many

different places. Majithia can be taken on remand again after the documents are recovered. Bikram Singh Majithia was brought to Mohali court amid tight security. Apart from the convoy of vehicles, police was deployed at various places on the road. During this time, Majithia supporters and Akali Dal workers tried to reach the court, but they were stopped on the way. Majithia has been sent to Nabha jail till July 19. Meanwhile, Shiromani Akali Dal has accused Punjab Police of keeping party leaders under house arrest. Sharing

some pictures on social media platform 'X', Akali Dal wrote, Bhagwant Mann government got nervous again before Bikram Singh Majithia's court appearance. Akali leaders were put under house arrest by sending police early in the morning, core committee member Jathedar Tirath Singh Mahala was put under house arrest. Similarly, the Akali Dal alleged that the police placed former minister and core committee member Sikander Singh Maluka under house arrest in village Maluka to prevent him from attending the hearing in Majithia's court.

1984 Operation Blue Star: Nishikant Dubey claims, 'Britain supported Indira Gandhi'

New Delhi, BJP MP Nishikant Dubey has made a sensational claim regarding the 1984 Golden Temple attack. He said that the then Prime Minister Indira Gandhi had attacked the Golden Temple in connivance with Britain. The BJP leader, citing an alleged report of the Home Secretary on his X handle, wrote, "The attack on the Golden Temple in 1984 was done in collaboration with Britain. British army officers were present in Amritsar. For the Congress, the Sikh community is just a toy." He also claimed that the agreement to hand over Kartarpur Sahib to Pakistan was signed by Sardar Swarn Singh in 1960, senior Congress leaders were protected to hide the 1984 massacre of Sikhs and Manmohan Singh was made a puppet Prime Minister in 2004. The



BJP shared an alleged confidential letter of the Home Secretary, claiming that Indian authorities had sought advice from Britain on removing Sikh extremists from the Golden Temple. This letter was written by Brian Faull, Private Secretary to the Foreign and Commonwealth Office, to Hugh Taylor, Private Secretary to the then Home Secretary. Through this letter, Nishikant has substantiated his claim. It says, the

Ghaziabad: Fire broke out in Pluto Hotel, 5 fire brigade vehicles brought it under control



Ghaziabad, Two incidents of fire were reported in Ghaziabad district of Uttar Pradesh on Monday. After the incident of fire in a paper factory located in Sahibabad, an incident of fire was also reported in a hotel. After which five fire department vehicles worked hard to control the fire. Fire was reported at 5:29 am in Pluto Hotel located in Sahibabad, Ghaziabad. No casualties have been reported in this incident. According to the fire department, at that time the vehicles of Sahibabad fire station were busy extinguishing the fire in a paper factory in Site-4. As soon as the fire was reported in the hotel, the Chief Fire Officer of Ghaziabad immediately sent the fire officers of Kotwali and Vaishali to the spot with 5 fire tenders and units. Upon reaching the scene, the fire department staff found the

fire in the hotel's rooftop kitchen, store and the hotel's elevation. The fire was intense, spreading rapidly and there was smoke everywhere. As there was no adequate way to reach the fire, the fire unit quickly spread a long hose line and started firefighting from the stairs on the other building behind the hotel and one to the front of the hotel. Seeing the magnitude of the fire, the surrounding area has been evacuated. Fire brigade vehicles have also been called from other districts to control this fire.

Khalistani terrorist Happy Pasiya will be brought to India from America, involved in more than 14 terrorist incidents

New Delhi/Chandigarh, The process of bringing notorious gangster and Khalistani terrorist Happy Pasiya, responsible for a series of terrorist attacks in Punjab, from the US to India is in its final stages. He will be brought to India soon. Happy, who has become the face of terror in Punjab during the years 2024 and 2025, was detained from Sacramento, America in April. He is currently in the custody of the American agency ISI. Happy Pasiya was taken into custody in America on 17 April. The NIA had announced a reward of Rs 5 lakh on Happy Pasiya's head. He is accused of carrying out more than 14 terror incidents in Punjab, including hand grenade attacks, targeting police stations and social media

posts taking responsibility for the blasts. According to sources, Happy Pasiya was in contact with Pakistan's intelligence agency ISI and Khalistani terrorist organizations like Babbar Khalsa International. He used to plot attacks with the aim of spreading instability in India, especially in Punjab. Happy's name cropped up in a series of grenade blasts and terrorist incidents in several districts of Punjab during 2024-25. Some major incidents:

November 24, 2024: A fence was erected outside the Ajnala police station.

November 27: Grenade attack on police post in Gurbaksh Nagar. December 2: Blast in Kathgarh police station of SC/ST Nagar, three terrorists arrested.

December 4: Explosion in Majitha police station, police said it was a tyre burst but later there was a dispute.

13 December: Grenade attack on Aliwal Batala police station, Pasiya claimed

responsibility. December 17: Blast in Islamabad police station, DGP considers it a terror attack. January 19, 2025: Blast at Guntala police station, Babbar Khalsa takes responsibility. February 3: Attack on Amritsar police post, police denies grenade attack. February 14: Blast in a policeman's house in Gurdaspur. March 15: Attack on temple by Thakur of Amritsar, main accused Gursiddak Singh killed in encounter. Punjab Police and central agencies, in collaboration with US security agencies, have prepared the necessary documents for the extradition of Pasiya. It is expected that he will soon be brought to India at Delhi airport, where he will be thoroughly questioned about the terrorist network and funding.

Tragic accident in Punjab: Uncontrolled bus overturned in the middle of the road in Dasuha, Hoshiarpur, 7 passengers died and 24 injured

Dasuha, A tragic road accident took place this morning in Dasuha, Hoshiarpur, Punjab. 7 people died in this horrific road accident. The accident took place near Sagara Adda near Hajipur Road in Dasuha. According to the information, a bus went out of control and overturned and so far 7 passengers have died in this accident. While it is being told that about 24 people have been injured. The injured have been admitted to the Civil Hospital of Dasuha. According to the information, after the uncontrolled bus overturned



on the road, there was a lot of screaming among the passengers. The people nearby informed the police and ambulance and started the rescue work. So far, the death of 7 passengers has been confirmed in the accident. The condition of many injured is said to be critical. This mini bus of private company Kartar Bus was going on Talwara Dasuha Road. Police has reached the spot and is investigating the matter.